भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1622

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

पीपीपी मोड पर एमएसएमई के लिए हब

1622. **श्रीमती डी. के. अरुणाः**

श्री इटेला राजेंदरः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर केंद्रों की स्थापना करने का है ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और पारंपरिक कारीगर अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकें और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार 60 क्लस्टरों में पारम्परिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निवेश-ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा कराने और उन्हें ऊर्जा के स्वच्छ रुपों में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अब तक स्वीकृत/व्यय की गई निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): वाणिज्य विभाग ने ई-कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच) के प्रमुख शुभारंभ के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। ये हब हितधारकों को एक स्थान पर एकत्रित रखते हैं ताकि ई-कॉमर्स निर्यात मंजूरी को सुव्यवस्थित किया जा सके और रिवर्स लॉजिस्टिक्स को सरल बनाया जा सके, जिससे ई-कॉमर्स के माध्यम से एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री कर सकें।

(ख) और (ग): विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने के लिए 60 क्लस्टरों में संचालित एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना की परिकल्पना की है, इस योजना के तहत, एमएसएमई को निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा (आईजीईए) करवाने में सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, इस योजना के तहत अभी तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।

*****